पोषण और अच्छे बजट की आवश्यकता

लेखक - जयश्री बी. एवं आर. गोपीनाथ
(एम.एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में कार्यरत)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (सामाजिक मुद्दे) से संबंधित है।

द हिन्दू

13 फरवरी, 2020

"जहाँ एक तरफ कुपोषण को चिन्हित करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित योजनाएँ हैं, वही दूसरी तरफ फंडिंग और पॉलिसी की कमी समस्या उत्पन्न कर रही है।"

कुछ महीने पहले, ग्लोबल हंगर इंडेक्स मे बताया कि भारत "गंभीर" भूख से पीड़ित है और 117 देशों की सूची में 102वें स्थान पर है और छह से 23 महीने के बीच के हर 10वें बच्चों को न्यूनतम स्वीकार्य आहार दिया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में पोषण के बारे में तत्परता परिलक्षित हुई, जहाँ उन्होंने समग्र पोषण या पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए प्रधानमंत्री अतिव्यापी योजना के तहत् विकास के अभूतपूर्व पैमाने का उल्लेख किया है, जिसमें 10 करोड़ परिवार शामिल हैं।

योजना और आवंटन

कुपोषण के कई आयाम हैं जिनमें कैलोरी की कमी, प्रोटीन की कमी और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी शामिल है। पोषण को चिन्हित करने का एक महत्त्वपूर्ण तरीका कृषि है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स द्वारा 2019 में शुरू किया गया भारतीय पोषण कृषि कोष इस अंतर को पाटने का एक हालिया प्रयास है। मौजूदा योजनाएँ भारत की कुपोषण दुविधा को अच्छी तरह से चिन्हित कर सकती हैं। अब सवाल उठता है कि इस चिंता को दूर करने में समस्याएँ कहाँ आ रही हैं? इसका उत्तर जानने के लिए हम बजटीय आवंटन और पिछले वर्ष में किए गए खर्च को समझने की कोशिश करेंगे।

सबसे पहला कैलोरी की कमी है। समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) योजना पूरक पोषण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवाएँ जिसमें बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को चिन्हित करती है तथा सामुदायिक कुपोषण को दूर करने के लिए प्रमुख समूह सहित सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करती है, जो कैलोरी की कमी उससे भी आगे की समस्याओं का समाधान करती है।

2019-20 के लिए, आवंटन 27,584.37 करोड़ रुपए था लेकिन संशोधित अनुमान 24,954.50 करोड़ रुपए हैं, जो संसाधनों के कम आंकलन की ओर इशारा करता है। इस वर्ष आवंटन थोड़ा अधिक है, लेकिन स्पष्ट रूप से कार्यान्वयन पर जोर दिया जाना चाहिए।

स्कूली बच्चों के पोषण को बढ़ाने के लिए भूख को चिन्हित करने का एक और मार्ग मिड-डे-मील योजना है। यहाँ भी, मुद्दा आवंटन के साथ नहीं बल्कि व्यय के साथ है। 2019-20 के बजट आवंटन में 11,000 करोड़ और संशोधित अनुमान केवल 9,912 करोड़ रुपए थे।

दूसरा है प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी को दूर करने में दलहन का बहुत बड़ा योगदान है। हालाँकि, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की योजना का उद्देश्य दालों को कल्याणकारी योजनाओं (मिड-डे मील, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ICDS) तक पहुँचाना है। उन्होंने 2019-20 के बजट में 800 करोड़ रुपए आवंटन की तुलना में केवल 370 करोड़ रुपए के अनुमान को संशोधित किया गया है।

अगला है सूक्ष्म पोषक तत्त्व की कमी। बागवानी मिशन (Horticulture mission) सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी को प्रभावी ढंग से दूर करने के तरीकों में से एक हो सकता है, लेकिन यहाँ भी कार्यान्वयन कम है। 2019-20 के लिए संशोधित अनुमान 2,225 करोड़ रुपए के आवंटन के मुकाबले 1,583.50 करोड़ रुपए है। 2018-19 में, भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय बाजरा मिशन की शुरुआत की, जिसमें देश भर में एक अभियान के रूप में पौष्टिक अनाज को बढ़ावा देने के लिए 2018-19 में बाजरा को "पोषक-अनाज" का नाम देना भी शुरू किया।

बजट में और साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) में इस पर और जोर दिया जा सकता है जिसमें बाजरा शामिल हैं। हालाँकि, NFSM 2019-20 के दौरान 2,000 करोड़ रुपए के आवंटन को लागू करने के लिए दबाव डालता है, क्योंकि संशोधित व्यय 1,776.90 करोड़ रुपए है। चूँकि कि बाजरा में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी को दूर करने की क्षमता है, इसलिए इन अनाजों को दी जाने वाली गति को बनाए रखने की जरूरत है।

पोषण अभियान की ओर बढ़ते हुए राष्ट्रीय पोषण मिशन जो कुपोषण को दूर करने के लिए एक बड़ी पहल है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में होने वाले कुल व्यय का 72% हिस्सा विकास के लिए वास्तविक समय की निगरानी और व्यवहार परिवर्तन के तहत सामान्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और घटकों पर व्यय को सक्षम करने में था। फंडिंग का सबसे अधिक ध्यान प्रौद्योगिकी पर रहा है, जो पोषण को चिन्हित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। पहल ने औसतन यह भी पाया कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए धन का केवल 34% वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2019-20 में 30 नवंबर, 2019 तक खर्च किया गया था।

एक समान योजनाओं का प्रभाव

आने वाले वर्षों में कम आवंटन, बजट बढ़ाने की संभावनाओं और पोषण योजनाओं पर ध्यान को सीमित करेंगे।

अगला कृषि-पोषण लिंक है, जो कि इस पहेली का एक और खंड है। जहाँ एक तरफ कृषि प्रारंभिक बजट भाषण पर हावी था, वही दूसरी तरफ कृषि और पोषण के बीच लिंक स्पष्ट नहीं था। यह कड़ी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत में लगभग ग्रामीण परिवार का 3/5वां हिस्सा कृषि रोजगार से जुड़ा हुआ है (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, 70वां दौर के अनुसार) और कुपोषण दर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के अनुसार) है, इसलिए कृषि-पोषण लिंकेज योजनाओं में अधिक प्रभाव और अधिक जोर देने की आवश्यकता है।

तो हम भारत में बेहतर पोषण कैसे ला सकते हैं? दुनिया में कुपोषित लोगों की सबसे बड़ी संख्या के साथ भारत को 2030 तक 'जीरो हंगर' के सतत् विकास लक्ष्य 2 को प्राप्त करने के लिए जल्दबाजी करने की आवश्यकता है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत को विशेष ध्यान देना चाहिए, बजट में कई मायनों में पोषण को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है।

लेखक के द्वारा इन सब समस्याओं को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं: डिजिटलीकरण से परे, पोषण संबंधी हस्तक्षेप पर ध्यान देना पोषण अभियान के अभिसरण घटक को तेज करना, पोषण को संबोधित करने के लिए सभी विभागों को एक स्थान पर लाने के लिए एक मंच का उपयोग करना; पोषण आधारित गतिविधियों के लिए 500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन की घोषणा करना; ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण-कृषि लिंक गतिविधियों के लिए युवा योजनाओं को बढ़ावा देना कृषि-पोषण से जुड़ी योजनाओं के लिए स्पष्ट जोर देना और फंड आवंटन; तथा धन के प्रारंभिक संवितरण और पोषण से जुड़ी योजनाओं का एक इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना।

पोषण सिर्फ आर्थिक, स्वास्थ्य, पानी की स्वच्छता, लैंगिक परिप्रेक्ष्य और सामाजिक मानदंडों के साथ बेहतर पोषण में योगदान देता है। यही कारण है कि कई योजनाओं के कार्यान्वयन बेहतर पोषण में योगदान कर सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि "भोजन केवल अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है बल्कि मानव पूँजी के विकास में एक आवश्यक घटक है और इसलिए राष्ट्रीय निर्माण के लिए पोषण महत्त्वपूर्ण है"। कुपोषण संज्ञानात्मक क्षमता, कार्यबल और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है अर्थात यह जीडीपी के 16% (विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व बैंक) को प्रभावित करता है।

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 में 117 देशों की सूची में 103वें स्थान पर है।
2. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय पोषण कृषि कोष की स्थापना की गई है।
3. भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए 2018-19 में राष्ट्रीय बाजरा मिशन प्रारंभ किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) केवल 2

(c) 1 और 3 (d) केवल 3

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements:

1. India is ranked 103rd in the list of 117 countries in the Global Hunger Index 2019.
2. The Indian Nutrition Agricultural Fund has been established by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.
3. The National Millet Mission has been launched by the Government of India in 2018-19 to address the deficiency of micronutrient elements.

Which of the above statements is / are incorrect?

(a) 1 and 2 (b) Only 2

(c) 1 and 3 (d) Only 3

नोट : 12 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. 'भारत में कुपोषण की समस्या का एक पहलू सम्बंधित योजनाओं के वित्तीयन में मौजूद अनियमितता भी है।'इस कथन का सोदाहरण विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

'One aspect of the problem of malnutrition in India is also the irregularity present in the funding of related schemes.' Analyze this statement with examples. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।

Comm